चेविटी वेंकन्ना यादव

बनाम

तेलंगाना राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 13604/2015)

24 अक्टूबर, 2016

[दीपक मिश्रा और शिवा कीर्ति सिंह, जे. जे.]

तेलंगाना (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम, 1966। 5 [तेलंगाना (कृषि उपज और पशुधन) बाजार (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथा संशोधित]-आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा कृषि बाजार समिति के गठन की वैधता-आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम, 1966 पर नए तेलंगाना राज्य के गठन के बाद (आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन पर), राज्य ने मूल अधिनियम में संशोधन करने के लिए 2014 का अध्यादेश संख्या 1 जारी किया। इसलिए धारा 5 में, समिति के सदस्यों की संख्या 18 से घटाकर 14 कर दी गई और बाजार समिति का कार्यकाल 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया-अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया कि मौजूदा सदस्य पद पर बने रहना बंद कर देंगे और सरकार व्यक्तियों को बाजार समिति की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्य करने के लिए सक्षम होगी-अध्यादेश को चुनौती दी गई-उच्च न्यायालय ने संशोधन को भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला माना क्योंकि बाजार समिति के मौजूदा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को समय से पहले हटाने की मांग की गई थी जो अन्यथा भावी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों के लिए उपलब्ध होंगे-निर्णय के बाद, राज्य ने धारा 5 में संशोधन के लिए 2015 का अध्यादेश संख्या 1 जारी किया। [इस दौरान अध्यादेश 1/2015, संशोधन अधिनियम

5/2015 के रूप में लागू हुआ जिसे तेलंगाना (कृषि उपज और पशुधन) बाजार (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जाता है] - संशोधन को 2015 से पूर्वव्यापी बनाया गया था और एक मान्य प्रावधान भी जोड़ा गया था-अध्यादेश को अपीलकर्ताओं द्वारा रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी-उच्च न्यायालय ने संशोधन को बरकरार रखने वाली याचिका को खारिज कर दिया-अपील पर, कहाः राज्य विधानमंडल को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानून में संशोधन करने की क्षमता थी-विधानमंडल को पूर्वव्यापी प्रभाव से 'नामित' शब्द द्वारा 'नियुक्त' शब्द को प्रतिस्थापित करने वाले विवादित संशोधन द्वारा, वर्तमान सदस्यों और भविष्य में आने वाले सदस्यों के बीच के अंतर को हटा दिया गया-इस प्रकार नामांकन द्वारा शुरू में की गई नियुक्ति को राज्य द्वारा उसकी खुशी पर समाप्त किया जा सकता है-ऐसा प्रावधान न तो संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है और न ही संविधान में निहित किसी सार्वजनिक नीति या लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करता है-संशोधित प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड के दुष्प्रभाव से ग्रस्त नहीं है, जहां तक बाजार समिति और विशेष बाजार समिति का संबंध है, जैसा कि दोनों विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14

विधानः सांविधिक अधिमूल्यांकन-आयोजितः जब कोई कानून पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियमित किया जाता है, तो यह न्यायिक शक्ति पर अतिक्रमण नहीं है जब विधायिका किसी न्यायिक उक्ति को सीधे रूप से निरस्त या उलट नहीं करती है-विधानमंडल, एक अधिनियम के माध्यम से, किसी न्यायालय के निर्णय को गलत या शून्य घोषित नहीं कर सकता है-हालाँकि, उसके पास अदालत के निर्णय में देखे गए कानून में किसी दोष को सुधारने की शक्ति है-जब ऐसा संशोधन किया जाता है, तो उसका उद्देश्य न्यायालय के निर्णय को उलटना नहीं है, बल्कि कानून की नींव और अर्थ को बदलने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से एक नया कानून बनाना है और उस आधार को

हटाना है जिस पर निर्णय की स्थापना की गई थी-यह विधायिका द्वारा वैधानिक अधिमूल्यांकन के बराबर नहीं है।

रंगीन विधान-रंगीन विधान के सिद्धांत में विधायिका की ओर से प्रामाणिक या दुर्भावनापूर्ण कोई सवाल शामिल नहीं है-पूरा सिद्धांत खुद को एक विशेष कानून बनाने के लिए एक विशेष विधानमंडल की क्षमता के सवाल में घूमता है-एक बार यह माना जाता है कि विधायिका के पास अपने विवेक के अनुसार कानून बनाने की शक्ति है, और वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम एक सह/हमारे योग्य अभ्यास है।

विधायिका की क्षमता-उस अवधि से एक कानून बनाने के लिए जब विधायिका स्वयं मौजूद नहीं थी-आयोजितः विधायिका के अस्तित्व में आने के बाद, इसके पास संवैधानिक मापदंडों के भीतर किसी भी कानून को पूर्वव्यापी या संभावित रूप से लागू करने की क्षमता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया:-

1. विधायिका के अस्तित्व में आने के बाद, उसके पास संवैधानिक मापदंडों के भीतर किसी भी कानून को पूर्वव्यापी या संभावित रूप से लागू करने की क्षमता है। [पैरा 23) [706-बी]

मिस. रतन लाल एंड कंपनी और ए. एन. आर. आदि बनाम निर्धारण प्राधिकरण, पटियाला और ए. एन. आर. ए. आई. आर. 1970 एससी 1742: 1969 एस. सी. आर. 544-पर निर्भर था।

2.1 शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित विधायी और न्यायिक कार्यों के बीच एक सीमांकन है। विधायिका के पास कानूनों को लागू करने की शक्ति है जिसमें पूर्वव्यापी रूप से कानूनों में संशोधन करने की शक्ति शामिल है और इस तरह

प्रभावहीनता या अयोग्यता के कारणों को हटा दिया जाता है। जब कोई कानून पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियमित किया जाता है, तो इसे न्यायिक शक्ति पर अतिक्रमण नहीं माना जाता है जब विधायिका किसी न्यायिक उक्ति को सीधे खारिज या उलट नहीं करती है। विधायिका, एक अधिनियम के माध्यम से, अदालत के किसी निर्णय को गलत या अमान्य घोषित नहीं कर सकती है, लेकिन क़ानून या प्रावधान में संशोधन कर सकती है ताकि इसे अतीत में लागू किया जा सके। विधायिका के पास एक संशोधन के माध्यम से, कानून में एक दोष को सुधारने की शक्ति है जो अधिनियम में देखा गया है और यहां तक कि अदालत के फैसले में भी उजागर किया गया है। कानून को विधायी इरादे के अनुरूप लाने और अदालत द्वारा बताए गए दोष को ठीक करने की इस पूर्ण शक्ति का उपचारात्मक और बेअसर करने वाला प्रभाव हो सकता है। जब इस तरह का सुधार किया जाता है, तो इसके पीछे का उद्देश्य अदालत के फैसले को रद्द करना या न्यायिक क्षेत्र का अतिक्रमण करना नहीं है, बल्कि केवल कानून की नींव और अर्थ को बदलने और उस आधार को हटाने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक नया कानून बनाना है, जिसके आधार पर निर्णय दिया गया है। यह विधायिका द्वारा वैधानिक अधिनिर्णय के बराबर नहीं है। इस तरह, न्यायालय का पूर्व निर्णय अस्तित्वहीन हो जाता है और नए विधान की व्याख्या के लिए अप्रवर्तनीय हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए कानून को उसके गुण-दोष और इस सवाल पर परखा और चुनौती दी जा सकती है कि क्या विधायिका के पास विचाराधीन विषय पर कानून बनाने की क्षमता है, लेकिन अति-पहुंच या रंगीन कानून के आधार पर नहीं। [पैरा 29) [709-ई-एच; 710-ए-बी]

2.2 एक बार जब यह माना जाता है कि विधायिका के पास अपने विवेक के अनुसार कानून बनाने की शक्ति है, और वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम एक रंगीन अभ्यास है। रंगीन विधान के सिद्धांत में

विधायिका की ओर से प्रामाणिकता या दुर्भावना का कोई सवाल शामिल नहीं है। पूरा सिद्धांत एक विशेष कानून को लागू करने के लिए एक विशेष विधायिका की क्षमता के सवाल में घूमता है। यदि विधायिका किसी विशेष कानून को पारित करने के लिए सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वे वास्तव में अप्रासंगिक हैं, जब तक कि वे, संशोधित अवतार में, संविधान के किसी भी अनुच्छेद को अस्वीकार नहीं करते हैं। [पैरा 30) [710-सी-डी]

श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका और अन्य। (1969) 2 एससीसी 283:1970 (1) एससीआर 388; तारा प्रसाद सिंह और अन्य। v. भारत संघ और अन्य। (1980) 4 एस. सी. सी. 179:1980 (3) एस. सी. आर. 1042; टी. एन. राज्य बनाम अरूरन शुगर लिमिटेड (1997) 1 एससीसी 326:1996 (8) पूरक। एस. सी. आर. 193-अनुसरण किया गया।

भुवनेश्वर सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। (1994) 6 एस. सी. सी. 77:1994 (1) पूरक। एस. सी. आर. 639; सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड बनाम भुवनेश्वर सिंह और अन्य। (1984) 4 एस. सी. सी. 429:1985 (1) एस. सी. आर. 618; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम नारायण सिंह (2009) 13 एस. सी. सी. 165:2009 (10) एस. सी. आर. 821; धरणदत्त और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2004) 1 एस. सी. सी. 712:2003 (6) पूरक एस. सी. आर. 151-पर निर्भर था।

3.1 उच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले में इस आधार पर संशोधित प्रावधान को खारिज कर दिया था कि सदस्यों, उपाध्यक्षों और अध्यक्षों के पद पर मौजूदा नियुक्तियों और भावी नियुक्तियों के बीच भेदभाव था। उच्च न्यायालय ने राय दी थी कि दोनों श्रेणियों के बीच वर्गीकरण उचित नहीं था और यह संविधान के अनुच्छेद 14 को असहज करता है। इसने हटाने के लिए वैधानिक सुरक्षा उपायों पर जोर दिया

था। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद विधायिका ने प्रावधान में संशोधन किया है और इस तरह मौजूदा सदस्यों और भविष्य में आने वाले सदस्यों के बीच के अंतर को हटा दिया है। इसने "नियुक्त" शब्द को "नामित" शब्द से प्रतिस्थापित किया है। सदस्यों का चुनाव नहीं किया गया। उन्हें किसी भी प्रकार के चयन द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। इन्हें राज्य सरकार द्वारा कुछ श्रेणियों में से चुना गया था। सदस्यों की स्थिति को "नियुक्त" शब्द को "नामित" शब्द के साथ प्रतिस्थापित करके संशोधित किया गया है। इस प्रकार, विधायिका ने पूर्वव्यापी रूप से अर्थ बदल दिया है। इसलिए, संशोधन के आधार पर, एक नामित सदस्य के लिए जो कार्यकाल कम किया गया है, वह एक अलग आधार पर खड़ा है। यदि नियुक्ति प्रारंभ में नामांकन द्वारा की गई है, तो संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हो सकता है, यदि विधायिका राज्य सरकार को अपनी इच्छानुसार ऐसी नियुक्ति को समाप्त करने और उनके स्थान पर नए सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत करती है। इस तरह का प्रावधान न तो संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है और न ही यह संविधान में निहित किसी सार्वजनिक नीति या लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है। [पैरा 31] (710-ई-एच; 711-ई-एच]

ओम नारायण अग्रवाल और अन्य बनाम नगर पालिका, शाहजहांपुर और अन्य। (1993) 2 एससीसी 242: 1993 (2) एस. सी. आर. 34-पर निर्भर था।

3.2 विधायिका ने अपने विवेक में "नियुक्ति" शब्द को प्रतिस्थापित किया है और इसे "पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नामांकन" बनाया है। इसे अवधि को कम करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए, हटाने की प्रक्रिया बरकरार रहती है। एक नामांकित व्यक्ति अवधि समाप्त होने पर समय के प्रवाह से कार्यालय से जा सकता है। यह उस समय की तुलना में अलग है जब उसे हटाया जाता है। प्रेजेंटी में एक नामित सदस्य को भी इस अवधि के दौरान प्रक्रिया को अपनाकर हटाया जा सकता है। अन्यथा, वह

अपना कार्यकाल समाप्त होने तक जारी रहेगा और कार्यकाल एक वर्ष का होगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि संशोधन के कारण अपीलार्थियों के निहित अधिकार प्रभावित हुए हैं। [पैरा 32) [712-ए-सी)

4. बाजार समिति और विशेष बाजार समिति की संरचना, कार्य और उद्देश्य अलग-अलग होते हैं। वे मूल रूप से विभिन्न श्रेणियों में आते हैं। उन्हें अनुच्छेद 14 के पैमाने में तौलना मुश्किल है। समानता खंड प्रभावित नहीं होता है। समितियों की विशेषताएँ भिन्न होने के कारण, अनुच्छेद 14 आकर्षित नहीं होता है। [पैरा 33] [712-डी]

डी. एस. रेड्डी बनाम कुलाधिपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय और अन्य। (1967) 2 एस. सी. आर. 214; पी. वेणुगोपाल बनाम भारत संघ (2008) 5 एस. सी. सी. 1:2008 (8) एस. सी. आर. 1-निर्दिष्ट

(1967) 2 एस. सी. आर. 214 2008 (8) एस. सी. आर. 1 1969 एस. सी. आर. 544 मामला कानून संदर्भ पैरा 8 पैरा 8 पैरा 23 पर निर्भर है।

1970 (1) एस. सी. आर. 388 ने पैरा 24 1994 (1) सप्लीमेंट का अनुसरण किया। एस. सी. आर. 639 पैरा 25 1980 (3) एस. सी. आर. 1042 के बाद पैरा 25 1985 (1) एस. सी. आर. 618 पैरा 26 2009 (10) एस. सी. आर. 821 पैरा 27 1996 (8) सप्लीमेंट पर निर्भर था। एस. सी. आर. 193 ने पैरा28 2003 (6) सप्लीमेंट का अनुसरण किया। एस. सी. आर. 151 पैरा30 1993 (2) एस. सी. आर. 34 पैरा 31 पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 13604/2015

2015 के डब्ल्यू. पी. सं. 11512 में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से

साथ में

2015 का सी. ए. सं. 13613

वी. वी. एस. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, के. परमेश्वर और सुश्री विजयश्री पटनायक, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, के. रामकृष्ण रेड्डी, महाधिवक्ता, मोहन राव, एस. उदय कुमार सागर और टी. वी. रत्नम, प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

दीपक मिश्रा, न्यायाधीश

1. इन अपीलों में, विशेष अनुमति द्वारा, अपीलकर्ताओं ने रिट याचिकाओं के एक समूह में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की कानूनी स्वीकार्यता पर सवाल उठाया है, जिसमें खंड पीठ ने आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार (संशोधन) अधिनियम, 2015 (संक्षिप्तता के लिए, "अधिनियम") की धारा 5 की उप-धारा (3) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

2. उच्च न्यायालय ने सुविधा के लिए, 2015 की डब्ल्यू. पी. संख्या 11512 में दिए गए तथ्यों को कहा है और इसलिए, हम उक्त रिट याचिका के तथ्यों का विज्ञापन करेंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि सभी रिट याचिकाओं में कथन मूल रूप से समान हैं।

3. उक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं को राज्य द्वारा 3 साल की अवधि के लिए कृषि बाजार समितियों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि वीडियो गो। आंध्र प्रदेश सरकार ने अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (I) और (2) के साथ पठित धारा 6 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि

बाजार समिति, कुबेर, आदिलाबाद जिले का गठन किया, जिसमें एक बी. चंद्र शेखर अध्यक्ष और अन्य सदस्य थे। यह उल्लेख किया गया कि उक्त बी. चंद्र शेखर को अध्यक्ष और एक डी. दत्ताराम को उपाध्यक्ष और 16 अन्य को सदस्यों के रूप में नामित किया गया था। इसी तरह की अधिसूचनाएँ अन्य कृषि बाजार समितियों के संबंध में दिनांकित अधिसूचनाओं 04.03.2013, 31.08.2013, 18.11.2013, 27.11.2013 के माध्यम से जारी की गईं और इस तरह के नामांकन के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में नामित व्यक्ति और सदस्य अपने-अपने कार्यों में बने रहे।

4. दिनांक 02/06/2014 को तेलंगाना राज्य को पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य से अलग कर दिया गया था और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 [2014 का अधिनियम 6] (जिसे इसके बाद "पुनर्गठन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के आधार पर उक्त तिथि से राज्य का दर्जा लागू हुआ। नए राज्य के गठन के बाद तेलंगाना के राज्यपाल ने अधिनियम में संशोधन के लिए 2014 का अध्यादेश संख्या 1 जारी किया और उक्त अध्यादेश के आधार पर अधिनियम की धारा 5 में दो बड़े बदलाव किए गए। बाजार समिति में सदस्यों की कुल संख्या 18 से घटाकर 14 कर दी गई और बाजार समिति का कार्यकाल 3 से घटाकर 2 साल कर दिया गया। अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया था कि मूल अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, मौजूदा सदस्य पद पर बने रहना बंद कर देंगे और सरकार बाजार समिति की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों को करने के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने में सक्षम होगी।

5. विवाद को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, अध्यादेश के प्रासंगिक भाग को नीचे प्रस्तुत किया गया हैः -

"2. तेलंगाना (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम, 1966 (जिसे इसके बाद प्रमुख अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 5 में (धारा 5 का संशोधन, (1966 का अधिनियम संख्या 16)) (I) की उप-धारा (I) (क) में प्रारंभिक पैराग्राफ में "अठारह सदस्य" शब्दों के स्थान पर "चौदह सदस्य" शब्द रखा जाएगा।

(ख) खंड (i) में "ग्यारह सदस्य" शब्दों के स्थान पर "आठ सदस्य" शब्द रखे जाएँगे; (ग) दूसरे परंतुक में "पाँच सदस्य" शब्दों के स्थान पर "तीन सदस्य" शब्द रखे जाएँगे; (घ) खंड (ii) में "तीन सदस्य" शब्दों के स्थान पर "दो सदस्य" शब्द रखे जाएँगे;

(2) उप-धारा (3) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएँगे।

3. बाजार समिति के मौजूदा सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद पर बने रहना बंद कर देंगेः (एल) मूल अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, तेलंगाना (कृषि उपज और पशुधन) बाजार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के प्रारंभ में पद धारण करने वाली प्रत्येक बाजार समिति के सभी सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद पर बने रहना बंद कर देंगे और इसके बाद सरकार के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने और बाजार समिति के कार्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगी जब तक कि इस अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार बाजार समिति का पुनर्गठन नहीं किया जाता है। **(जोर दिया गया)**

6. अध्यादेश जारी होने के बाद, कृषि और सहयोग विभाग (MKT.I) ने G.O.MS. संख्या 11 दिनांक । 8.08.2014 के माध्यम से निम्नलिखित आदेश पारित कियाः -

> "ऊपर पढ़े गए संदर्भ 3 में जारी एक अध्यादेश के अनुसरण में और आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के खंड (3) के अनुसार, मौजूदा बाजार समितियों के सभी सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। आयुक्त और कृषि विपणन निदेशक, तेलंगाना, हैदराबाद को प्रत्येक बाजार समिति की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों को करने के लिए तत्काल प्रभाव से एक व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि तेलंगाना (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम, 1966 की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार बाजार समिति का फिर से गठन नहीं किया जाता है, जैसा कि ऊपर 3 में एक अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया है।
>
> 2. कृषि आयुक्त और निदेशक। विपणन, तेलंगाना, हैदराबाद तदनुसार मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई करेंगे।"

7. अध्यादेश और उस आधार पर पारित परिणामी आदेश को 2014 की रिट याचिका संख्या 24877 और उच्च न्यायालय के समक्ष संबंधित मामलों में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि खंड 3 के माध्यम से सभी याचिकाकर्ताओं को विधायी कार्रवाई के माध्यम से हटाना भेदभावपूर्ण था क्योंकि सदस्यों, उपाध्यक्षों और अध्यक्षों के कार्यालय में भविष्य में नियुक्त व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 5,6,6 (ए) और 6 (बी) के तहत प्रदान किए गए मौजूदा प्रावधानों

के तहत उनकी शक्तियों को हटाने या अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी थे, जबकि रिट याचिकाकर्ताओं को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियात्मक सुरक्षा को समय से पहले हटाने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया कि रिट याचिकाकर्ताओं को एक वर्ग के रूप में चुना गया था और उनके साथ भविष्य के सदस्यों, उपाध्यक्षों और अध्यक्षों के समान वर्ग की तुलना में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, क्योंकि हटाने का समान प्रावधान भविष्य के सदस्यों, उपाध्यक्षों और अध्यक्षों पर लागू नहीं किया गया था, जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा के हकदार हैं। उस आधार पर यह राय दी गई कि संशोधित प्रावधान ने संविधान के अनुच्छेद 14 को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह मौजूदा सदस्यों, बाजार समिति के उपाध्यक्षों और अध्यक्षों और उसी समिति के भावी सदस्यों के बीच अंतर के संबंध में समझ से बाहर था, जिसके लिए उन्हें हटाने के संबंध में अलग प्रावधान की परिकल्पना की गई है। अंततः उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया किः -

> "हम मानते हैं कि अध्यादेश के खंड-3 को सम्मिलित करके उपरोक्त प्रावधान करके याचिकाकर्ताओं और उनमें से प्रत्येक के साथ नग्न भेदभाव किया गया है। दूसरे शब्दों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की गारंटी नहीं दी गई है। याचिकाकर्ताओं को अपने कार्यकाल और अध्यक्ष सदस्यों के रूप में उनके कामकाज के संबंध में भविष्य के समकक्ष के समान उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) (5) (7), 6 (ए) और 6 (आर) द्वारा मनमाने ढंग से, सनकी तरीके से हटाने के खिलाफ संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। समानता के इस अधिकार को उपरोक्त खंड द्वारा छीन लिया गया है।"

8. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने डी. एस. रेड्डी बनाम कुलाधिपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय और ओ. टी. एल. 1सं1 और पी. वेणुगोपाल बनाम भारत संघ में निर्णयों का उल्लेख किया और आगे इस प्रकार राय दीः -

> "हाथ के मामले में, निश्चित रूप से, यह एक एकल उम्मीदवार नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों का एक समूह है जो समान रूप से पीड़ित और समान रूप से तैनात थे और जिन्हें एक वर्ग में रखा गया था और एक ही कार्यालय में अन्य समूहों से अलग व्यवहार किया गया था, अर्थात्, भविष्य के सदस्य और बाजार समिति के पदाधिकारी। इसलिए, हम रिट याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार करते हुए यह निर्णय देते हैं कि विद्वान महाधिवक्ता का मानना है कि उक्त अध्यादेश का खंड-3 संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। तदनुसार, उसी को निरस्त कर दिया जाता है। इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए और निरस्त करते हुए, इसके अनुसार जारी किया गया परिणामी सरकारी आदेश भी अमान्य और अवैध है, इसे भी रद्द कर दिया गया है और याचिकाकर्ताओं और उनमें से प्रत्येक को उनके संबंधित पदों पर बहाल किया जाएगा। हम तदनुसार सरकार को तुरंत ऐसा करने का निर्देश देते हैं।"

9. 2014 की रिट याचिका संख्या 24877 और संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, तेलंगाना सरकार ने अध्यादेश संख्या 24877 जारी किया। अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करने के लिए 2015 का । दिनांक 13.02.2015। अध्यादेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसने नोटिस जारी किया और बाजार समिति के कामकाज के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। [नियत समय पर, 2015 का संशोधन अधिनियम संख्या 5 लागू हुआ। उक्त संशोधन

अधिनियम को तेलंगाना (कृषि उपज और पशुधन) बाजार (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जाता है। उक्त संशोधन अधिनियम को 01.01.2012 से पूर्वव्यापी बनाया गया है। संशोधन अधिनियम धारा 5, एस. ए., 6,11,22 और 33 में संशोधन करता है। उच्च न्यायालय ने सारणीबद्ध रूप में 1966 के मूल अधिनियम और संशोधन अधिनियम के तहत वैधानिक योजना का उल्लेख किया है। हम मूल अधिनियम और संशोधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित समझते हैं। मूल अधिनियम की धारा 5 (1) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक बाजार समिति में अठारह सदस्य होंगे और सरकार द्वारा उसमें निर्धारित तरीके से अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया जाएगा। धारा 5 (1) (i) में निर्धारित किया गया है कि सरकार द्वारा उसके बाद उल्लिखित कुछ श्रेणियों में से विपणन निदेशक के परामर्श से ग्यारह सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, अर्थात् कृषि उपज के उत्पादक जो छोटे किसान हैं, छोटे किसानों के अलावा अन्य कृषि उपज के उत्पादक, अधिसूचित क्षेत्रों में पशुधन और पशुधन उत्पादों के मालिक। मूल अधिनियम ने कुछ श्रेणियों के संबंध में कुछ सदस्यों को प्रदान किया जिन्हें संशोधन अधिनियम द्वारा बदल दिया गया है। हमें इसका विस्तार से विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है। मूल अधिनियम की धारा 5 (2) में बाजार समिति की संरचना का प्रावधान किया गया था और इसे एक अलग भाषा में लिखा गया था। मूल अधिनियम की धारा 5 (2) नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः -

> "(2) प्रत्येक बाजार समिति का एक अध्यक्ष उप-धारा (1) के खंड (1) में निर्दिष्ट अपने सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा और उपाध्यक्ष की नियुक्ति उप-धारा (1) के खंड (1) या खंड (2) में निर्दिष्ट अपने सदस्यों में से सरकार द्वारा विपणन निदेशक के परामर्श से की जाएगी।

10. मूल अधिनियम की धारा 5 (3) ने उप-धारा (1) के तहत नियुक्त सदस्यों के पद की अवधि के बारे में निर्धारित किया। धारा 5 की उप-धाराएँ (3), (5), (6) और (7) जो आई. एस. के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैंः -

> "(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, उप-धारा (I) के तहत नियुक्त सदस्यों की पदावधि नियुक्ति की तारीख से तीन साल होगीः बशर्ते कि उप-धारा (I) के खंड (ii) के तहत नियुक्त कोई सदस्य पद धारण करना बंद कर देगा, यदि वह व्यापारी नहीं रह जाता हैः
>
> बशर्ते कि बाजार समिति का कोई गैर-सरकारी सदस्य अपने पद पर बने रहना बंद कर देगा यदि वह समिति की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, जिसमें ऐसी बैठकें भी शामिल हैं जो गणपूर्ति के अभाव में आयोजित नहीं की जा सकती थीं।
>
> स्पष्टीकरणः- दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, बाजार समिति की कोई भी बैठक जिसमें कोई सदस्य स्वयं अनुपस्थित हो, उसके खिलाफ नहीं मानी जाएगी यदि उस बैठक की उचित सूचना उसे नहीं दी गई थी।
>
> (5) सरकार, अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा सकती है, जो अपनी राय में इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत जारी किए गए वैध आदेशों के किसी भी नियम या उपनियमों को जानबूझकर छोड़ देता है या उनका पालन करने से इनकार करता है या अवज्ञा करता है या स्पष्टीकरण का अवसर देने के बाद अपने पद

या अपने में निहित शक्ति का दुरुपयोग करता है, और उक्त अधिसूचना में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के कारणों का विवरण होगा।

(6) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से उप-धारा (5) के तहत हटाया गया कोई भी व्यक्ति धारा 6 की उप-धारा (।) के तहत बाजार समिति के अगले पुनर्गठन की तारीख तक उक्त कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा।

(7) बाजार समिति के किसी अन्य सदस्य को सरकार द्वारा किसी भी समय ऐसे कारणों से और ऐसी जांच के बाद पद से हटाया जा सकता है, जो निर्धारित किया जाए।

11. मूल अधिनियम की धारा 6 में इस प्रकार प्रावधान किया गया हैः-

"धारा 6। बाजार समिति का पुनर्गठनः-(1) सरकार बाजार समिति के सदस्यों के पद की अवधि या उप-धारा (2) के तहत विस्तारित अवधि की समाप्ति पर बाजार समिति का पुनर्गठन करेगी।

(2) सरकार बाजार समिति के सदस्यों के कार्यकाल को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकती हैः बशर्ते कि ऐसा कोई विस्तार एक बार में छह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा।

(3) (क) जहाँ किसी भी कारण से विलम्ब होता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाजार समिति का गठन या पुनर्गठन, सरकार या विपणन निदेशक बाजार समिति के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक नियुक्त कर सकता है जब तक कि बाजार समिति का पुनर्गठन नहीं हो जाता।

(ख) इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या व्यक्ति, सरकार के नियंत्रण और ऐसे निर्देशों या निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो वे समय-समय पर जारी करें, शक्तियों का प्रयोग करेंगे, कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और बाजार समिति के कार्यों का पालन करेंगे और ऐसी सभी कार्रवाई करेंगे जो बाजार समिति के हित में आवश्यक हों।

(ग) सरकार इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को देय पारिश्रमिक निर्धारित कर सकती है।

(घ) सरकार किसी भी समय, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाजार समिति के गठन या पुनर्गठन की व्यवस्था कर सकती है। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या व्यक्ति ऐसे गठन या पुनर्गठन पर बाजार समिति के मामलों का प्रबंधन करना बंद कर देंगे।"

12. राज्य सरकार और विपणन निदेशक को बाजार समिति के अध्यक्ष को निलंबित करने, अध्यक्ष की शक्ति को वापस लेने और कुछ अन्य व्यवस्थाएं करने का अधिकार देने वाले अन्य प्रावधान थे जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

13. संशोधन अधिनियम सं. 2015 की 5 को 13 अप्रैल, 2015 को राज्यपाल की मंजूरी मिली। धारा 1 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि यह 01.01.2012 से प्रभावी माना जाएगा। मूल अधिनियम की धारा 5 में संशोधन इस प्रकार हैः-

"(1) उप-धारा (1) में-(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में" अठारह "शब्द के स्थान पर" चौदह "शब्द रखा जाएगा; (ख) खंड (1) में" ग्यारह "शब्द के स्थान पर" आठ "शब्द और" नियुक्त "शब्द के स्थान पर" नामित

"शब्द रखा जाएगा; (ग) खंड (1) के दूसरे परंतुक में" पाँच "शब्द के स्थान पर" तीन "शब्द रखा जाएगा।

(घ) खंड (ii) में "तीन" शब्द के स्थान पर "दो" शब्द और "नियुक्त" शब्द के स्थान पर क्रमशः "मनोनीत" शब्द रखा जाएगा।

(ङ) खंड (iii) में "नियुक्त" शब्द के स्थान पर "मनोनीत" शब्द रखा जाएगा।

(2) उप-धारा (2) में, दो स्थानों पर आने वाले "नियुक्त" शब्द के स्थान पर "मनोनीत" शब्द रखा जाएगा;

(3) उप-धारा (3) के स्थान पर इसके तहत पहले परंतुक के साथ निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः

"(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर,

उप-धारा (I) के तहत नामित सदस्यों की पदावधि नामांकन की तारीख से एक वर्ष होगी; बशर्ते कि उप-धारा (I) के खंड (ii) के तहत नामित कोई सदस्य पद धारण करना बंद कर देगा, यदि वह व्यापारी नहीं रह जाता है।

(4) उप-धारा (6) में "नियुक्ति" शब्द के स्थान पर "नामांकन" शब्द रखा जाएगा। (5) उप-धारा (9) में "नियुक्त" शब्द के स्थान पर "मनोनीत" शब्द रखा जाएगा;

(6) उप-धारा (10) में "नियुक्ति" शब्द के स्थान पर "मनोनीत" शब्द रखा जाएगा; (7) उप-धारा (10) के बाद निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् -

"(11) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित समिति के सदस्य सरकार की इच्छा के दौरान पद धारण करेंगे।"

14. मूल अधिनियम की धारा 6 में कुछ संशोधन किए गए हैं जो नीचे दिए गए हैंः -

"((i) खंड (क) में "नियुक्त कर सकते हैं" शब्दों के स्थान पर "नामित कर सकते हैं" शब्द रखे जाएँगे;

(ii) खंड (ख) में "नियुक्त" शब्द के स्थान पर "नामित" शब्द रखा जाएगा।

((ग) खंड (ग) में "नियुक्त" शब्द के स्थान पर "नामित" शब्द रखा जाएगा;

(iv) खंड (घ) में-(क) "नियुक्ति" शब्दों के स्थान पर "नामांकन" शब्द रखा जाएगा; (ख) दो स्थानों पर आने वाले "नियुक्त" शब्द के स्थान पर "नामित" शब्द रखा जाएगा।"

15. इसी तरह, मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (I) में, "नियुक्त" शब्द को "नामित" शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। मूल अधिनियम के खंड (ए) में उप-धारा (2) की धारा 33 में, "नियुक्त" शब्द को "नामित" शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। जहां भी मूल अधिनियम में "नियुक्ति", "नियुक्त" और "नियुक्त" शब्दों का उपयोग किया गया है, उन्हें क्रमशः "नामांकन", "नामित" और "नामित" शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है। सत्यापन से संबंधित प्रावधान, जो धारा 33 का एक हिस्सा है, निम्नानुसार हैः -

"इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित समिति के सदस्य, जिनका

कार्यकाल इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत समाप्त हो रहा है, उनका कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पद पर बने रहना, सभी मामलों में मान्य है, जैसे कि उन्हें उक्त अवधि के लिए वैध रूप से नामित किया गया है।"

16. उच्च न्यायालय के समक्ष, जैसा कि आक्षेपित आदेश से पता चलता है, मुख्य चुनौती अधिनियम की धारा 5 को दी गई थी, जिसके तहत संशोधन अधिनियम में पूर्वव्यापी प्रभाव देकर बाजार समिति का कार्यकाल तीन साल से घटाकर एक साल कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि संशोधन अधिनियम का संशोधन अधिनियम और धारा 5 (3) के पूर्वव्यापी संचालन के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ कोई तर्क या संबंध नहीं है, जिसने इस शब्द को कम कर दिया है, यह प्रत्यक्ष रूप से अवैध, भेदभावपूर्ण है और पूर्ण अनुचितता से ग्रस्त है। एक तर्क प्रस्तुत किया गया कि जहां तक बाजार समितियों का संबंध है, संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है क्योंकि विशेष बाजार समितियों को कार्यकाल में इस तरह की कमी से बाहर रखा गया है।

17. यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि मामले के अंतिम निपटारे के दौरान, उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक चरण में तैयार किए गए प्रश्न पर ध्यान दिया जो इस प्रकार हैः - "क्या विधानमंडल एक अधिनियम बनाते समय संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर सकता है और तेलंगाना राज्य के गठन से पहले की तारीख से संशोधन अधिनियम का पूर्वव्यापी संचालन संविधान के प्रावधानों की जांच के लिए खड़ा है।"

18. यह भी आग्रह किया गया कि बाजार समिति के कार्यकाल को कम करना न केवल एक अनुचित कार्य था, बल्कि पिछले अवसर पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए

फैसले के खिलाफ भी था, क्योंकि सत्यापन से संबंधित प्रावधान ने फैसले के आधार को नहीं हटाया है।

19. राज्य की ओर से, उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि राज्य विधानमंडल की क्षमता को चुनौती देने के अभाव में, याचिकाकर्ताओं की दलीलें स्वीकार्य नहीं थीं। जहां तक विधायिका की क्षमता का संबंध है, यह भी आग्रह किया गया कि तेलंगाना राज्य विधानमंडल इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है और समग्र राज्य में प्रचलित सभी अधिनियमों में संशोधन करने का हकदार है। राज्य की ओर से यह प्रचार किया गया कि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ मौजूदा कानून में संशोधन असंवैधानिक नहीं होगा। बाजार समिति और विशेष बाजार समिति के बीच की गई तुलना के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं और वास्तव में, केवल कुछ विशेष बाजार समितियों का गठन किया गया था।

20. उच्च न्यायालय ने बार में प्रस्तुत की गई दलीलों की सराहना करते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य के विधानमंडल को पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने से पहले पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून बनाने का अधिकार है; जिसमें याचिकाकर्ताओं को जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है; कि संशोधित प्रावधान न्यायिक शक्ति को हड़प नहीं लेते हैं और ये प्रावधान न तो मनमाने हैं और न ही भेदभावपूर्ण हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 के किसी भी अंग को आहत नहीं करते हैं। इस दृष्टिकोण के कारण, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

21. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री के. परमेश्वर के साथ विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. वी. एस. राव और प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील श्री एस. उदय कुमार सागर के साथ विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरी को सुना है।

22. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम सोचने के लिए तैयार हैं, निम्नलिखित मुद्दे चित्रण के लिए उत्पन्न होते हैंः

क) क्या राज्य विधानमंडल राज्य के अस्तित्व में आने से पहले की अवधि के लिए कानून बना सकता था?

ख) क्या निर्णय के प्रभाव को मिटाने के लिए पहले के निर्णय के आधार को हटा दिया गया है?

ग) क्या संशोधन के कारण निहित अधिकार प्रभावित हुए हैं?

घ) क्या संशोधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता खंड के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं?

23. हम पहले बिंदु पर चर्चा करेंगे। पुनर्गठन अधिनियम 02.06.2014 पर लागू हुआ। प्रस्तुतिकरण, उक्त तिथि से पहले, वह विधानमंडल जो एक इकाई के रूप में अस्तित्व में नहीं था, पूर्व अवधि को शामिल करने वाले किसी पहलू से संबंधित कानून नहीं बना सकता था। उपरोक्त निवेदन हमें लंबे समय तक नहीं रोकेगा। मिस में। रतन लाल एंड कंपनी और एक अन्य आदि बनाम निर्धारण प्राधिकरण, पटियाला और एक अन्य न्यायालय राज्य के पुनर्गठन से पहले एक संशोधन के माध्यम से हरियाणा राज्य द्वारा अधिनियमित कानून से संबंधित हरियाणा राज्य की क्षमता से निपट रहा था। इस संदर्भ में न्यायालय ने कहाः -

> "यह तर्क दिया जाता है कि राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर, 1966 को हुआ था और इसके कुछ हिस्सों में संशोधन मूल अधिनियम को इस तारीख से पहले की तारीख से संशोधित करने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में, किसी एक राज्य का विधानमंडल समग्र राज्य द्वारा पारित कानून में संशोधन करना चाहता है। यह तर्क पुनर्गठन के बाद

मूल अधिनियम की स्थिति को पूरी तरह से गलत समझता है। वह अधिनियम अब प्रत्येक क्षेत्र में एक स्वतंत्र अधिनियम के रूप में लागू होता है और उस क्षेत्र में विधायिका की विधायी क्षमता के अधीन है। उस राज्य के क्षेत्र के संबंध में नए राज्यों में अधिनियम में संशोधन किया गया है और यह अकल्पनीय है कि यह क्षमता के भीतर नहीं हो सकता है। यदि तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह अधिनियम तब तक अपरिवर्तनीय रहेगा जब तक कि समग्र राज्य एक बार फिर अस्तित्व में नहीं आता। राज्य पुनर्गठन अधिनियमों की योजना नए राज्यों में उपयुक्त विधानमंडल द्वारा प्रतिस्थापित, संशोधित या परिवर्तित किए जाने तक नए क्षेत्रों पर लागू होती है। विधायिका ने यही किया है और इस तरह के संशोधन के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता है।

उपरोक्त परिच्छेद यह स्पष्ट करता है कि विधायिका के अस्तित्व में आने के बाद, उसके पास संवैधानिक मापदंडों के भीतर पूर्वव्यापी या संभावित रूप से किसी भी कानून को लागू करने की क्षमता है।

24. दूसरा मुद्दा जो विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या पहले के फैसले का आधार वास्तव में हटा दिया गया है। तथ्यात्मक अंक बताने से पहले यह बताना आवश्यक है कि इस न्यायालय ने उक्त सिद्धांत को कैसे देखा है। श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका और अन्य मामले में संविधान पीठ ने उस कानून पर विचार करते हुए, जिसका उद्देश्य कानून द्वारा अवैध घोषित कर को मान्य करना है, राय दी कि जब कोई विधानमंडल किसी अदालत द्वारा अप्रभावी या अमान्य कानून के तहत अवैध रूप से एकत्र किए गए कर को मान्य करने के लिए निर्धारित करता है, तो सत्यापन को प्रभावी ढंग से होने से पहले प्रभावहीनता या

अयोग्यता के कारण को हटा दिया जाना चाहिए। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि विधानमंडल के पास कर लगाने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है, तो कार्रवाई कभी भी अप्रभावी और अवैध बनी रहेगी। मान लीजिए कि विधायी क्षमता, केवल यह घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि-न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा, क्योंकि यह न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णय को उलटने के समान है जो विधानमंडल के पास नहीं है या प्रयोग नहीं करता है। अदालत का निर्णय हमेशा बाध्यकारी होना चाहिए जब तक कि जिन शर्तों पर यह आधारित है, उनमें इतना मौलिक परिवर्तन नहीं किया जाता है कि परिवर्तित परिस्थितियों में निर्णय नहीं दिया जा सकता था। इसके बाद, न्यायालय ने कहा कि इस तरह से अवैध घोषित कर का सत्यापन केवल तभी किया जा सकता है जब अवैधता या अयोग्यता के आधार को हटाया जा सके और वास्तव में हटा दिया जाए और इस प्रकार कर को कानूनी बना दिया जाए। विधायिका इसे कई तरह से करती है। यह जिन तरीकों को अपना सकता है, उनमें से एक है उस कानून का अपना अर्थ और व्याख्या देना जिसके तहत कर एकत्र किया गया था और विधायी आदेश द्वारा अदालतों पर बाध्यकारी नया अर्थ बनाता है। इस तरह का कानून लाए जाने पर, यह पहले के निर्णय के प्रभाव को बेअसर कर देता है जिसके परिणामस्वरूप यह अप्रभावी हो जाता है। किसी विधि की वैधता का परीक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि क्या विधानमंडल के पास वह क्षमता है जिसका वह विषय-वस्तु पर दावा करता है और क्या सत्यापन करने में यह उस दोष को दूर करता है जिसे अदालतों ने मौजूदा कानून में पाया था और कर के वैध अधिरोपण के लिए सत्यापन कानून में पर्याप्त प्रावधान करता है।

25. भुवनेश्वर सिंह और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में कोकिंग कोयला खान (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1971 की धारा 3, जिसे वर्ष 1971 में लागू किया गया था, को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त

अभिरक्षक ने कोकिंग कोयला खानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और उक्त खदानें 17.10.1971 से 30.04.1972 की अवधि के दौरान अभिरक्षक के माध्यम से केंद्र सरकार के प्रबंधन में रहीं। कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 ई. से लागू हुआ। 1.5.1972, और कोकिंग कोयला खदानों के संबंध में मालिकों का अधिकार, स्वामित्व और हित केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया और सभी बाधाओं से मुक्त कर दिया गया। उक्त अधिनियम के प्रावधानों को इस न्यायालय के समक्ष तारा प्रसाद सिंग इट और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में चुनौती दी गई थी और संविधान पीठ ने उक्त अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता ने शिकायत की कि कस्टोडियन ने कोयले को उठाने के खर्च को डेबिट किया था, जबकि कोकिंग कोयला खदान कस्टोडियन के प्रबंधन में थी, लेकिन उठाए गए कोयले की मात्रा के लिए कीमत जमा नहीं की थी, जो केंद्र सरकार के तहत निहित उक्त कोयला खदान की तारीख से पहले स्टॉक में पड़ी थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और एक निर्देश जारी किया गया कि खाते को फिर से तैयार किया जाए और याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाए। विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि इस न्यायालय का विचार था कि संरक्षक द्वारा खदान के प्रबंधन की अवधि के दौरान लाभ और हानि का निर्धारण करने के लिए निर्धारित तिथि के प्रारंभ में पड़े निकाले गए कोयले के भंडार की बिक्री मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोयला क्षेत्रों द्वारा दायर अपील खारिज किए जाने के बाद, कोयला खान राष्ट्रीयकरण कानून (संशोधन) अध्यादेश, 1986 जारी किया गया और बाद में कोयला खान राष्ट्रीयकरण कानून (संशोधन) अधिनियम, 1986 लागू हुआ। संशोधन अधिनियम की धारा 4 द्वारा, उप-धारा (2) कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 10 में पेश की गई थी। उक्त प्रावधान ने घोषणा की कि केंद्र सरकार द्वारा किसी भी कोकिंग कोयला

खदानों या उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में निर्दिष्ट कोकिंग कोयला खदानों के समूह के खिलाफ पहली अनुसूची के पांचवें कॉलम में निर्दिष्ट राशियों को उप-धारा (।) के तहत अपने मालिक को दिया जाना आवश्यक है, और यह हमेशा शामिल माना जाएगा कि स्टॉक में कोयले या धारा 3 के खंड (जे) में निर्दिष्ट अन्य संपत्तियों के संबंध में ऐसे मालिक को नियत दिन से तुरंत पहले भुगतान की जाने वाली राशि और ऐसे कोयले या अन्य संपत्तियों के संबंध में मालिक को कोई अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। धारा 19 मान्य करने वाला प्रावधान था।

26. रिट याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर उक्त अध्यादेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई थी कि यह सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड बनाम भुवनेश्वर सिंह और अन्य के मामले में दिए गए फैसले को रद्द करने के लिए है।

> " ... यदि धारा 10 में कोयला खान राष्ट्रीयकरण कानून (संशोधन) अधिनियम, ।986 द्वारा शुरू की गई उप-धारा (2) स्थापना के समय से ही मौजूद थी, तो उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के लिए उस कीमत को ध्यान में रखने के लिए निर्देश जारी करने का कोई अवसर नहीं था जो नियत दिन से पहले की तारीख को पड़े कोक के स्टॉक के लिए देय थी। पूर्वव्यापी प्रभाव से उपरोक्त अधिनियम की धारा 10 में उप-धारा (2) को लागू करने के अधिकार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। एक बार संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से पेश किए जाने के बाद, अदालतों को इस आधार पर कार्य करना होगा कि ऐसा प्रावधान शुरू से ही था। इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला को देखते हुए डीमिंग प्रावधान की भूमिका पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए धारा 19 के साथ धारा 10 की उप-धारा (2) को पढ़कर यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थियों को उस अवधि के

दौरान लेखांकन के उद्देश्य से नियत दिन से पहले की तारीख को पड़े कोक के भंडार को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, जब विचाराधीन खदान केंद्र सरकार के प्रबंधन में थी, क्योंकि यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता को दिए गए मुआवजे में नियत दिन से पहले की तारीख को भंडार में पड़े ऐसे कोयले की कीमत शामिल थी। कोयले के ऐसे भंडार के लिए न तो कोई मुआवजा दिया जाना है और न ही कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उप-धारा (।) के उद्देश्य के लिए इसकी कीमत को ध्यान में रखा जाना है।

इस दृष्टिकोण के कारण, अदालत ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।"

27. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम नारायण सिंह में क़ानून के सत्यापन पर विचार करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया किः -

"इसलिए यह स्पष्ट है कि जहां एक सक्षम विधायी प्रावधान है जो पूर्वव्यापी रूप से किसी निर्णय की नींव के आधार को हटा देता है, उक्त अभ्यास एक वैध विधायी अभ्यास है बशर्ते कि यह किसी अन्य संवैधानिक सीमा का उल्लंघन न करे।"

28. उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य टी. एन. बनाम अरूरन शुगर लिमिटेड में संविधान पीठ के फैसले से पुनः प्रस्तुत किया, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः -

"यह विधायिका के लिए खुला है कि वह अदालत द्वारा बताए गए दोष को दूर करे या अधिनियम की परिभाषा या किसी अन्य प्रावधान को

पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करे। इस प्रक्रिया में यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायपालिका की शक्ति पर विधायिका द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अदालत के निर्देश को हमेशा बाध्यकारी होना चाहिए जब तक कि जिन शर्तों पर यह आधारित है, उन्हें इतना मौलिक रूप से परिवर्तित नहीं किया जाता है कि परिवर्तित परिस्थितियों में ऐसे निर्णय नहीं दिए जा सकते थे। इसमें विचाराधीन निर्णय में बताए गए कानून में दोष को हटाना, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन या प्रतिस्थापन शामिल होगा, जिस पर ऐसा निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ आधारित है।"

29. उपरोक्त अधिकारियों से, यह तय किया जाता है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित विधायी और न्यायिक कार्यों के बीच एक सीमांकन है। विधायिका के पास कानूनों को लागू करने की शक्ति है जिसमें पूर्वव्यापी रूप से कानूनों में संशोधन करने की शक्ति शामिल है और इस तरह प्रभावहीनता या अयोग्यता के कारणों को हटा दिया जाता है। जब कोई कानून पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियमित किया जाता है, तो इसे न्यायिक शक्ति पर अतिक्रमण नहीं माना जाता है जब विधायिका किसी न्यायिक उक्ति को सीधे खारिज या उलट नहीं करती है। विधायिका, एक अधिनियम के माध्यम से, अदालत के किसी निर्णय को गलत या अमान्य घोषित नहीं कर सकती है, लेकिन क़ानून या प्रावधान में संशोधन कर सकती है ताकि इसे अतीत में लागू किया जा सके। विधायिका के पास एक संशोधन के माध्यम से, कानून में एक दोष को सुधारने की शक्ति है जो अधिनियम में देखा गया है और यहां तक कि अदालत के फैसले में भी उजागर किया गया है। कानून को विधायी इरादे के अनुरूप लाने और अदालत द्वारा बताए गए दोष को ठीक करने की इस पूर्ण शक्ति का एक उपचारात्मक और तटस्थ प्रभाव हो सकता है। जब इस तरह का सुधार किया जाता है, तो इसके

पीछे का उद्देश्य अदालत के फैसले को रद्द करना या न्यायिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करना नहीं है, बल्कि केवल कानून की नींव और अर्थ को बदलने और उस आधार को हटाने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक नया कानून बनाना है जिस पर निर्णय स्थापित किया गया है। यह विधायिका द्वारा वैधानिक अधिनिर्णय के बराबर नहीं है। इस तरह, न्यायालय का पूर्व निर्णय अस्तित्वहीन हो जाता है और नए विधान की व्याख्या के लिए अप्रवर्तनीय हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए कानून को उसके गुण-दोष और इस सवाल पर परखा और चुनौती दी जा सकती है कि क्या विधायिका के पास विचाराधीन विषय पर कानून बनाने की क्षमता है, लेकिन अति-पहुंच या रंगीन कानून के आधार पर नहीं।

30. एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि विधायिका के पास अपने विवेक के अनुसार कानून बनाने की शक्ति है, और वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, यह तर्क कि अधिनियम एक रंगीन अभ्यास है, विफल होना चाहिए और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। धरम दत्त और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि रंगीन विधान के सिद्धांत में विधानसभाओं की ओर से प्रामाणिक या दुर्भावनापूर्ण होने का कोई सवाल शामिल नहीं है। पूरा सिद्धांत एक विशेष कानून को लागू करने के लिए एक विशेष विधायिका की क्षमता के सवाल में घूमता है। यदि विधायिका किसी विशेष कानून को पारित करने के लिए सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने इसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वे वास्तव में अप्रासंगिक हैं, जब तक कि वे संशोधित अवतार में संविधान के किसी भी अनुच्छेद को अस्वीकार नहीं करते हैं।

31. ऐसा कहने के बाद, यह जांच की जानी चाहिए कि क्या पहले के फैसले का आधार हटा दिया गया है। उच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले में संशोधित प्रावधान को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि सदस्यों, उपाध्यक्षों और अध्यक्षों के पद पर मौजूदा नियुक्तियों और भविष्य में नियुक्तियों के बीच भेदभाव था। उच्च

न्यायालय ने राय दी थी कि दोनों श्रेणियों के बीच वर्गीकरण उचित नहीं था और यह संविधान के अनुच्छेद 14 को असहज करता है। इसने हटाने के लिए वैधानिक सुरक्षा उपायों पर जोर दिया था। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद विधायिका ने प्रावधान में संशोधन किया है। इस तरह के संशोधन से मौजूदा सदस्यों और भविष्य में आने वाले सदस्यों के बीच के अंतर को हटा दिया गया है। इसने "नियुक्त" शब्द को "नामित" शब्द से प्रतिस्थापित किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि पहले के प्रावधान के अनुसार सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में कृषि उपज के उत्पादकों, पशुधन के मालिकों और पशुधन के उत्पादों की कुछ श्रेणियों में से विपणन निदेशक के परामर्श से सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। सरकार द्वारा विपणन निदेशक के परामर्श से अपने सदस्यों में से अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। जैसा कि पहले कहा गया है, "नियुक्त" शब्द को "मनोनीत" के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राव का निवेदन है कि इस तरह के संशोधन से अपीलार्थियों के निहित अधिकार प्रभावित हुए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की योजना के तहत, "नियुक्त" शब्द जैसा कि पहले के प्रावधान में उपयोग किया गया था, वास्तव में ऐसी नियुक्ति नहीं थी जिसे सेवा न्यायशास्त्र के तहत किसी पद के बराबर माना जा सके। सदस्यों को बाजार समिति के गठन के उद्देश्य से सदस्य होना था। आग्रह किया जाता है कि सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का एक निश्चित कार्यकाल था, जिन्हें जांच के बाद या कुछ शर्तों के तहत हटाया जा सकता था। हमारा ध्यान धारा 6 की उप-धारा (5) की ओर आकर्षित किया गया है, लेकिन संशोधन के बाद सदस्यों ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले, यानी तीन साल, सदस्य बनना बंद कर दिया था। हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि राज्य सरकार का सक्षम प्राधिकारी अभी भी अवधि समाप्त होने से पहले अन्य प्रावधानों का सहारा लेते हुए सदस्य या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को हटा सकता है। अपीलार्थियों की शिकायत है कि अवधि में

कटौती की गई है और निहित अधिकार प्रभावित हुआ है। तर्क यह है कि यह प्रावधान के पूर्वव्यापी संशोधन द्वारा नहीं किया जा सकता था। उपरोक्त तर्क एक भ्रांति से ग्रस्त है। सदस्यों का चुनाव नहीं किया गया। उन्हें किसी भी प्रकार के चयन द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। इन्हें राज्य सरकार द्वारा कुछ श्रेणियों में से चुना गया था। सदस्यों की स्थिति को "नियुक्त" शब्द को "नामित" शब्द के साथ प्रतिस्थापित करके संशोधित किया गया है। इस प्रकार, विधायिका ने पूर्वव्यापी रूप से अर्थ बदल दिया है। हमारी सुविचारित राय में, संशोधन के आधार पर, एक नामित सदस्य के लिए जो कार्यकाल कम किया गया है, वह एक अलग आधार पर खड़ा है। ओम नारायण अग्रवाल और अन्य बनाम नगर पालिका, शाहजहांपुर और अन्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि शुरुआत में नामांकन द्वारा नियुक्ति की गई है, तो संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हो सकता है, यदि विधायिका राज्य सरकार को अपनी इच्छानुसार ऐसी नियुक्ति को समाप्त करने और उनके स्थान पर नए सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नामित सदस्यों के पास नगर निगम बोर्ड के किसी भी निवासी की वसीयत या अधिकार नहीं होता है जैसा कि एक निर्वाचित सदस्य के मामले में मौजूद हो सकता है। अदालत ने आगे कहा कि इस तरह का प्रावधान न तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है और न ही यह संविधान में निहित किसी भी सार्वजनिक नीति या लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है।

32. "नियुक्ति" शब्द को "नामांकन" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यह नामांकन द्वारा नियुक्ति है। यह प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से कुछ श्रेणियों से है। यह नियुक्ति नहीं है जैसा कि सामान्य रूप से शब्द का अर्थ है। विधायिका ने अपने विवेक में "नियुक्ति" शब्द को प्रतिस्थापित किया है और इसे "पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नामांकन" बनाया है। इसे अवधि को कम करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए,

हटाने की प्रक्रिया बरकरार रहती है। एक नामांकित व्यक्ति अवधि समाप्त होने पर समय के प्रवाह से कार्यालय से जा सकता है। यह उस समय की तुलना में अलग है जब उसे हटाया जाता है। प्रेजेंटी में एक नामित सदस्य को भी इस अवधि के दौरान प्रक्रिया को अपनाकर हटाया जा सकता है। अन्यथा, वह अपना कार्यकाल समाप्त होने तक जारी रहेगा और कार्यकाल एक वर्ष का होगा। निहित अधिकार की याचिका स्पेन में एक महल के निर्माण के समान है। इसके पास खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं हैं और इसलिए, हम उक्त समर्पण को बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटाते हैं।

33. अंतिम मुद्दा जो उठा है वह बाजार समिति और विशेष बाजार समितियों के संबंध में विभिन्न प्रकार के चित्रण से संबंधित है। इनकी रचना, कार्य और उद्देश्य अलग-अलग हैं। वे मूल रूप से विभिन्न श्रेणियों में आते हैं। उन्हें अनुच्छेद 14 के पैमाने में तौलना मुश्किल है। समानता खंड, हमारे सुविचारित विचार में, प्रभावित नहीं है। समितियों की विशेषताएँ भिन्न होने के कारण, अनुच्छेद 14 आकर्षित नहीं होता है। इस प्रकार, उक्त समर्पण आधारहीन है।

34. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम इन अपीलों में किसी भी योग्यता को नहीं समझते हैं और तदनुसार, उन्हें खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

कल्पना के. त्रिपाठी याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक **मनीष शर्मा** द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है,एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।